(b) and (c) The State Government of Assam have been requested to look into the genuine grievances of tribals of the area and to make conscious efforts to create a feeling of participation by giving them sence of belonging to Assam.

Seizure of VHS cassettes in Connaught Place, New Delhi

208. SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that police have seized a large number of VHS cassettes during a recent raid conducted in the Palika Bazar, Connaught Place, New Delhi;

(b) whether it is also a fact that many shopkeepers have managed to replace the recorded casettes with blank cassettes in connivance with the Station House Officer, Connaught Place, New Delhi; and

(c) if so, whether any inquiry has been initiated against the erring official and if not, the reasons thereforp

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

राष्ट्रीय उद्यानों की परिधि से आदिवासी लोगों का विस्थापन

209. **श्री अजीत जोगी :**
श्री पृथ्वी माझी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यमान नियमों में राष्ट्रीय उद्यानों की परिधि के अन्दर रहने वाले आदिवासी लोगों को हटाने के लिए कोई उपबंध है;

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों से अब तक कितने आदिवासी लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और उनके पुनर्वास के लिए क्या प्रबंध किये गये हैं;

(ग) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि विस्थापित किये गये आदिवासी लोगों को ठीक ढंग से पुनः नहीं बसाया गया है जिसके कारण उन्हें अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी कठिनाईयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जैड़० आर० अंसारी) : (क) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उपबंधों में राष्ट्रीय पार्क में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि के संबंध में राज्य को सभी अधिकार दिये जाने की व्यवस्था है। इससे उन व्यक्तियों का पार्क से बाहर पुनर्वास करना आवश्यक हो गया है जिनकी भूमि तथा अधिकार ले लिए गए हैं।

(ख) से (घ) सूचना राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकारों से एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कताई मिलों को लाइसेंसों का जारी किया जाना

210. **श्री अजीत जोगी :**
श्री पृथ्वी माझी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र को कताई मिलों के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर "ना" हो, तो क्या सहकारी क्षेत्र को नये लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश में सहकारी क्षेत्र की कताई मिलों को नए लाइसेंस जारी किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम): (क) से (घ) गैर सरकारी क्षेत्र / सहकारी क्षेत्र में कताई मिलें स्थापित करने के लाइसेंसों का मुद्दा, दिनांक 19-3-1985 के प्रेस नोट सं० 8 तथा दिनांक 30-6-1988 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 629 में निहित मार्ग निदेशों द्वारा संचालित होता है। दिनांक